you want to say something, you can respond now. Otherwise, you can take note of it and respond later.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, the only thing that I can tell you is that all of us have deep commitment to the supreme sacrifice of Bhagat Singh. A particular fact has been brought to our notice. I will correct it and I will surely consult my colleague in the Government. Our Government is fully dedicated to give all the respect to the supreme sacrifice of Bhagat Singh, Sukhdev and others.

Problems faced by students due to Current Promotion Policy

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, अभी भगत सिंह जी का उल्लेख हुआ है, जो तरुणाई के द्योतक थे। मैं उन लाखों छात्रों के बारे में बात करना चाहता हूं, जो पिछली प्रणाली और पिछली व्यवस्था के कारण प्रभावित हुए हैं। उनको पिछले समय में कक्षाओं में आगे बढ़ाने की जो पद्धति लागू की गई थी, उसके कारण आठवीं कक्षा के बाद नौवीं कक्षा मे उत्तीर्ण होने और उनके ज्ञान का स्तर बढ़ा हुआ न होने के कारण लाखों छात्रों को या तो स्कूल छोड़ना पड़ता है या उनको निराशा झेलनी पड़ती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसे लाखों छात्रों के भविष्य के बारे में वह विचार करे और जब से यह प्रणाली लागू हुई कि बिना परीक्षा के उनको उत्तीर्ण करना है, तब से प्रभावित ऐसे लाखों छात्रों के भविष्य के बारे में कोई सुनिश्चित योजना बनाए। हालांकि आने वाले समय में सरकार इस पर विचार कर रही है कि परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, किन्तु मेरी चिन्ता यह है कि जो छात्र अभी प्रभावित हो गए हैं और जिनको आठवीं के बाद परीक्षाओं में पास होने का मौका नहीं मिला है, उन लाखों छात्रों के बारे में हम क्या योजना बना रहे हैं, जिससे देश की तरुणाई को निराशा न हो और उन्हें अपने भविष्य को बनाने के लिए एक नया मार्गदर्शन मिले। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। मानव संसाधन विकास मंत्री कुछ कहना चाहते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): सर, इस बारे में सभी राज्यों से बहुत विचार-विमर्श के बाद सदन के सामने एक बिल पेश है कि पाँचवीं और आठवीं कक्षा में स्कूल में ही छात्रों की परीक्षा ली जाए और यह परीक्षा लेने का अधिकार भी हर राज्य को दिया जाएगा। यह CABE में unanimously तय हुआ है। अभी माननीय सदस्य ने जो बताया है, उस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि वे ही उस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के सामने अभी यह बिल है। वे जल्दी इसको देखें, तो यह सदन के सामने आएगा।

डा. सत्यनारायण जटियाः विषय यह नहीं है, बल्कि विषय यह है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः ठीक है। अब आप दोनों बाकी बातें आपस में कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. सत्यनारायण जटियाः जो प्रभावित छात्र हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई कैसे होगी? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः प्लीज़। सत्यनाराण जटिया जी, आप सीनियर हैं न! ...**(व्यवधान)**...

Need to take back the decision of complete disinvestment of the Dredging Corporation of India

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO (Telangana): Mr. Chairman, Sir, the Government's decision to sell the entire stake of 75 per cent in a Mini-Ratna, Dredging Corporation of India (DCI), is detrimental to the interests of the nation. The DCI shall not be treated as another PSU which can be invested for the purpose of economic viability. Our country is having a coastline of 7,500 kilometres, 13 major ports and approximately 200 notified and intermediate ports which require continuous capital and maintenance dredging. The dredging sector is having a vast future perspective as comprehensive dredging is required in future in the entire coastline to control and mitigate natural disasters apart from giving a boost to the economy. The DCI is having an access to the entire coast of the country and thus plays a pivotal role in the security of the country. Actually, DCI shall be part of the Indian Navy under the control of the Ministry of Defence and shall be made part of the coastal and maritime security.

The decision of the Union Cabinet to completely sell the Dredging Corporation of India to private operators not only creates a monopoly of the private operators in the dredging sector but also becomes a threat to the nation's security. Further, the life and future of employees, workers and their families who are eking out their livelihood and striving to develop the DCI since four decades, fall in jeopardy if the Government sells the entire stake in the DCI. The Core Group of Secretaries and the NITI Aayog which have recommended complete privatization of DCI have not conducted an indepth study of the national security concerns of the dredging activity in a country having the longest coast as its border and also future prospects of the dredging sector in the economical growth of the country.

Sir, I, therefore, request the Government to bring the issue of complete disinvestment of DCI before the Parliament for a detailed discussion in the interest of the nation. Thank you, Sir.